2

भारतीय डेयरी विकास: भविष्य की चुनौतियां और रणनीतियां

आर.बी. काले[1], के. पोन्नूसामी[2], एम.एस. मीना[3] एवं एस.के. सिंह[4]

1. प्रस्तावना
2. देसी नस्ल के पशुओं की उत्पादकता बढ़ाना
3. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और उचित उपयोग
4. पशु चिकित्सा सुविधाओं में सुधार
5. दूध विपणन संरचना
6. पशु चिकित्सा विस्तार की भूमिका में सुधार

1. प्रस्तावना

भारतीय डेयरी क्षेत्र ने दूध उत्पादन में 8 गुना से अधिक वृद्धि हासिल कि है, जो 1950–51 से 17 करोड़ टन से बढ़कर 2015–16 में 155 मिलियन टन हो गया है। वर्तमान में प्रति व्यक्ति उपलब्धता (322 ग्राम प्रति दिन), 280 ग्राम प्रति दिन की अपेक्षा से अधिक है, यद्यपि भविष्य की मांग, बढ़ते हुए प्रति व्यक्ति आय के कारण, आहार पद्धति बदलने, तेजी से शहरीकरण और बढ़ते आबादी के कारण उत्पादन की वृद्धि को पार कर जाएगी। उत्पादन में भारी वृद्धि के बावजूद, उत्पादकता और उत्पाद की गुणवत्ता की कमी और उत्पादन में क्षेत्रीय असमानताएं भारत में चिंता का एक कारण बनी हुई है। 2021–22 तक 200 से 210 मिलियन टन दूध की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए, भारत को पिछले 10 वर्षों में पंजीकृत 4.5 मिलियन टन के औसत उत्पादन के मुकाबले प्रति वर्ष 6 मिलियन टन अधिक दूध का उत्पादन करना होगा। भारत में दूध का बड़ा हिस्सा छोटे किसानों द्वारा निर्मित किया जा रहा है जो कुल दूध उत्पादन में 70 प्रतिशत से अधिक योगदान करते हैं। जब तक आवश्यक गति पर दूध उत्पादन नहीं बढ़ाते, तब तक दूध की आपूर्ति में अंतर अधिक होने की संभावना है और आयात पर निर्भरता हो सकती है। इस बीच, दूध उत्पादकों के लिए दूध का उत्पादन पर्याप्त रूप से फायदेमंद नहीं है इसलिए वे आजीविका के वैकल्पिक स्त्रोतों की तलाश कर रहे हैं। भारतीय डेयरी क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन दिख रहा है क्योंकि कई किसान खेती के अलावा आजीविका के अन्य स्त्रोतों की ओर जा रहे हैं। वर्ष 2001 से 2011 (2011 की जनगणना) के दौरान 9 दशलक्ष तक देश में किसानों की संख्या में गिरावट आयी है, जिसका मतलब है कि कम हाथों से अधिक मुंह को खिलाना होगा।

इसलिए दूध की भविष्य की मांग को पूरा करने, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने और डेयरी को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं।

2. देसी नस्ल के पशुओं की उत्पादकता बढ़ाना

राष्ट्रीय मवेशी आयोग ने सूचना दी कि आनुवांशिक सुधार के लिए पिछले कार्यक्रम सफल नहीं थे, खासकर देसी नस्लों का उन्नयन उन राज्यों में निरंतर संकर के माध्यम से किया गया, जहां खाद्य और चारा संसाधनों की

[1]वैज्ञानिक, भाकृअनुप–प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय, पूना, महाराष्ट्र ई–मेलः rkrajivndri@gmail.com; Mobile: 87428-04790
[2]प्रधान वैज्ञानिक, भाकृअनुप–राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा
[3]प्रधान वैज्ञानिक, भाकृअनुप–कृषि तकनीकी अनुप्रयोग संस्थान, जोधपुर, राजस्थान
[4]निदेशक, भाकृअनुप–कृषि तकनीकी अनुप्रयोग संस्थान, जोधपुर, राजस्थान

उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। इसलिए पशु प्रजनन नीति के पुनर्निरिक्षण करके विशिष्ट क्षेत्रीय दृष्टिकोण के साथ प्रयास किया जाना चाहिए, जो खाद्य और चारा संसाधनों की कमी वाले वर्षायुक्त क्षेत्रों में अच्छी स्वदेशी नस्लों के संरक्षण पर केंद्रित है। गुजरात में गिर, आंध्र प्रदेश में ओंगोल और पुणगणुर नस्लों, हरियाणा में साहिवाल और थारपारकर, कर्नाटक में अमृतमहल, केरल के वेचूर जैसी अधिक उत्पादन क्षमता वाली नस्लें भारत में हैं। अंधाधुंध संकर–प्रजनन की वजह से शुद्ध स्वदेशी नस्लों की जनसंख्या में कमी आई है। इस प्रकार, जहाँ शुद्ध स्वदेशी नस्लें पायी जाती हैं वहां विदेशी नस्लों के साथ संकर–प्रजनन प्रतिबंधित होना चाहिए। शुद्ध स्वदेशी नस्लों के सुधार के लिए किसानों का देसी नस्ल संरक्षण, संघों का गठन, रोग मुक्त व उच्च गुणवत्ता के नर का संरक्षण तथा उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

3. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और उचित उपयोग

तिलहन के केक के निर्यात पर प्रतिबंध होना चाहिए और गेहूं और अन्य फसलों के कटाई पर फसल काटने की मशीन का उपयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए जिससे कि पर्याप्त मात्रा में गेहूं का भूसा उपलब्ध हो। देश में पशुओं के लिए कोई चारा संसाधन प्रबंधन प्रणाली नहीं है। देश भर में चारा बैंक नेटवर्क की स्थापना से चारे की कमी वाले क्षेत्रों में चारा की उपलब्धि की जा सकती है। चारे की कमी होने वाले राज्यों में खनिज मिश्रणों का उपयोग, हाइड्रोपोनिक्स, अजोला, साइलेज, यूरिया उपचार जैसे बेहतर खाद्य और चारा प्रौद्योगिकियों को किसानों तक हस्तांतरण के लिए अधिक जोर दिया जाना चाहिए।

4. पशु चिकित्सा सुविधाओं में सुधार

किसानों तक पशुपालन के बारे में उचित जानकारी की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। अपर्याप्त पशु चिकित्सा सुविधाओं तथा पशु चिकित्सा कर्मचारियों की कमी भी असंतुलित प्रगति का कारण है। वर्तमान पशुधन जनगणना के अनुसार, देश को 1.16 लाख पशु चिकित्सक अधिकारियों की जरूरत है और केवल 63,000 पशु चिकित्सक अधिकारी, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के साथ पंजीकृत हैं, जिसका मतलब है कि मानव शक्ति में लगभग 50 प्रतिशत की कमी इसलिए पशु चिकित्सा विभाग में पशु चिकित्सक अधिकारियों की नियुक्ति पर प्राथमिकता देना चाहिए।

5. दूध विपणन संरचना

एक मजबूत संगठित दूध विपणन ढांचा केवल कुछ ही क्षेत्रों में तैयार हुआ है। इसलिए अन्य क्षेत्रों में डेयरी सहकारी संगठन के नेटवर्क के विकास के लिए और डेयरी को अधिक लाभप्रद बनाने के लिए किसान दूध उत्पादक कंपनियों के रूप में अधिक संगठित विपणन की नई पीढ़ी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

6. पशु चिकित्सा विस्तार की भूमिका में सुधार

पशु चिकित्सा विस्तार कार्यकर्त्ता की भूमिका जानवरों के उपचार के लिए सीमित है। इसलिए नई प्रौद्योगिकियों के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए उन्हें विस्तार कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए।

यह उपाय डेयरी उद्यम की स्थिति में सुधार करने के लिए और अंत में दूध की भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए दूध उत्पादन में सहायक होंगे ।